

भारतीय वनिरिमाण हेतु चीनी तकनीशयिन

प्रलमिस के लयि:

[उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन \(PLI\) योजना](#), [आत्मनरिभर भारत](#), [गलवान संघर्ष 2020](#), [प्रेस नोट 3 \(PN 3\)](#) के तहत FDI नीति, [आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24](#), [चाइना प्लस वन रणनीति](#), [गगि इकोनॉमी](#), [राष्ट्रीय शक्ति नीति, 2020](#), [आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन \(OECD\)](#) ।

मेन्स के लयि:

भारतीय अर्थव्यवस्था में तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सक्षम औद्योगिकी श्रमिकों की भूमिका तथा आवश्यकता ।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

हाल ही में चीनी तकनीशयिनों के लयि अल्पकालिक व्यावसायिक वीजा की मंजूरी की सुविधा हेतु एक पोर्टल ने कार्य करना शुरू कर दिया है ।

- यह सरकार की प्रमुख [उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन \(PLI\) योजना](#) के तहत उत्पादन इकाइयों को शुरू करने और क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लयि आवश्यक है ।

भारत को चीनी तकनीशयिनों की आवश्यकता क्यों है?

- **मशीनों के परिचालन में वलिंब:** घरेलू वनिरिमाण कंपनयिँ मशीनों को इनस्टॉल करने, मरम्मत और भारतीय श्रमिकों के प्रशिक्षण जैसे कार्यों हेतु आवश्यक चीनी तकनीशयिनों के लयि वीजा प्राप्ति में वलिंब के विषय में चर्चा जता रही है ।
- भारतीय नरिमाता चीनी तकनीशयिनों की मांग करते हैं, क्योंकि वे अन्य पश्चिमी या यहाँ तक कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के तकनीशयिनों की तुलना में अधिक वहनीय होते हैं ।
- **वैश्विक ऑर्डरों को पूरा करने में वलिंब:** चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स नरिमाताओं को वर्ष 2020 से अब तक 15 बलियन अमेरिकी डॉलर का उत्पादन घाटा और 1,00,000 नौकरयिों का नुकसान हुआ है ।
 - [इलेक्ट्रॉनिक्स वनिरिमाण उद्योग](#) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत ने 10 बलियन अमेरिकी डॉलर का नरियात अवसर भी खो दिया है तथा मूल्य संवर्धन में 2 बलियन अमेरिकी डॉलर की हानि हुई है ।
- **आत्मनरिभर भारत की उपलब्धि:** आवश्यक विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित करने से घरेलू वनिरिमाण इकाइयों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आयात पर नरिभरता कम करने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में सहायता मिलीगी ।
- **उत्पादन शुरू होने में देरी:** धीमी वीजा अनुमोदन प्रक्रिया के कारण कई उद्योगों में उत्पादन शुरू होने में देरी हुई है ।
 - [कपड़ा और चमड़ा](#) जैसे क्षेत्रों में जहाँ महत्त्वपूर्ण क्षमता है, मशीनरी महीनों से अप्रयुक्त रही है क्योंकि चीनी विक्रेताओं की मांग है कि केवल उनके कर्मचारी ही उन्हें शुरू करें ।

भारत चीनी तकनीशयिनों को वीजा देने में संशय क्यों कर रहा था?

- वर्ष 2020 में [गलवान में हुई झड़प](#) के बाद सीमा पर गतरिध के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर चीनी प्रभाव को सीमति करने के उद्देश्य से कई सरकारी कदम उठाए गए ।
 - वर्ष 2019 में चीनी नागरिकों को 2,00,000 वीजा प्राप्त हुए, लेकिन 2023 में, चीनी कर्मयिों को दयि जाने वाले वीजा की संख्या घटकर 2000 रह गई ।
- सरकार ने [प्रेस नोट 3 \(PN3\)](#), 2020 के तहत FDI नीति में भी संशोधन कयिा, जसिसे भूमि-सीमावर्ती देशों से नविश को सरकारी मार्ग के तहत लाया गया ।
 - [प्रेस नोट 3](#) में संशोधन के बाद से भारत ने जून 2023 तक चीन से प्राप्त कुल 435 FDI आवेदनों में से केवल एक चौथाई को ही मंजूरी दी है ।
- भारतीय नीति नरिमाताओं में सुरक्षा-संचालति मानसकित्ता उभरी है । 2024 में, चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स पेशेवरों के लयि मात्र 1000 वीजा भी “पाइपलाइन” में रुके हुए हैं, जो “गहन जाँच” से गुजर रहे हैं ।

भारत अपने लाभ हेतु चीन की विशेषज्ञता का उपयोग कैसे कर सकता है?

- **चीनी FDI प्रवाह में वृद्धि:** [आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24](#) में नरियात को बढ़ावा देने के लिये चीनी कंपनियों से निवेश को आकर्षित करने का समर्थन किया गया है।
 - वर्तमान में चीन अप्रैल 2000 से दिसंबर 2021 तक भारत में दर्ज कुल FDI इक्विटी प्रवाह में केवल 0.43% हिस्सेदारी या 2.45 बिलियन अमरीकी डॉलर के साथ 20वें स्थान पर है।
- **चाइना+1 रणनीति:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कहा गया है कि मैक्सिको, वियतनाम, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देश पश्चिमी फर्मों द्वारा अपनाई गई [चाइना+1 रणनीति](#) से लाभान्वित हो रहे हैं।
 - भारत अपने विशाल घरेलू बाज़ार, प्रतस्पर्द्धी श्रम लागत और सहायक सरकारी नीतियों के कारण चाइना+1 रणनीति से काफी लाभ उठा सकता है।
- **वैश्विक बाज़ार के साथ एकीकरण:** चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक वनरिमाण दगिगज और एक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक एवं तकनीकी अभिकर्त्ता है।
 - भारतीय वनरिमाण को बढ़ावा देने के लिये यह आवश्यक है कि भारत स्वयं को चीन की तरह [वैश्विक आपूर्ति शृंखला](#) में एकीकृत करे।

भारतीय औद्योगिक श्रमिकों से जुड़ा मुद्दा क्या है?

- **कम उत्पादकता:** चीनी पेशेवर "अत्यधिक उत्पादक" हैं। भारतीय उद्योग जगत के नेताओं के अनुसार, चीनी लोग उन्हीं संसाधनों से 150 वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, जिनसे भारतीय 100 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं।
- **कौशल अंतर:** चीनी और भारतीय कारखाना पर्यवेक्षकों और श्रमिकों के बीच "एक महत्त्वपूर्ण कौशल अंतर" मौजूद है।
 - भारतीय व्यवसायों ने चीन से मशीनें खरीदी हैं, लेकिन चीनी तकनीशियनों की सहायता के बिना उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने में उन्हें कठिनाई होती है, क्योंकि स्थानीय कार्यबल में उन्हें चलाने के लिये आवश्यक कौशल का अभाव है।
- **खराब औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम:** औद्योगिक संगठन अपने कर्मचारियों को वर्तमान औद्योगिक कौशल मांग को पूरा करने के लिये ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने पर केंद्रित अपने कर्मचारियों को ऑन-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने में विफल रहते हैं।
- **अप्रासंगिक पाठ्यक्रम:** शैक्षिक और कौशल कार्यक्रम प्रायः वर्तमान उद्योग की जरूरतों के अनुरूप नहीं होते हैं, जिससे छात्रों द्वारा सीखी गई बातों और नियोक्ताओं की जरूरतों के बीच अंतर उत्पन्न होता है।
 - जब तक [स्थानीय शिक्षा](#) में व्यापक रूप से सुधार नहीं किया जाता, तब तक बहुत सारी नौकरियों के साथ समृद्धि एक दुखद कल्पना बनी रहेगी।

भारत औद्योगिक क्षेत्र में कौशल विकास को कैसे बेहतर बना सकता है?

- **उत्प्रेरक के रूप में विदेशी ज्ञान:** पूर्वी एशियाई विकास की कहानी दर्शाती है कि [आर्थिक विकास के लिये विदेशी ज्ञान महत्त्वपूर्ण](#) है। 1980 के दशक में, कोरियाई व्यवसायों ने उन्हें नष्ट करने और रिवर्स इंजीनियर करने के लिये विदेशी मशीनें खरीदीं।
- **नरितर प्रशिक्षण:** किसी संगठन के भीतर नरितर प्रशिक्षण प्रदान करने से वर्तमान कर्मचारियों को अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने का अवसर मिलता है। यह नई तकनीकों और विधियों को अधिक सुव्यवस्थित रूप से अपनाने में मदद करता है।
- **कॉलेजों के साथ साझेदारी:** इंटरनशिप और अप्रेंटिसशिप के अवसरों के माध्यम से कॉलेज के छात्रों तक पहुँचना उन्हें मांग में प्रासंगिक कौशल का एक विचार देता है।
- **औद्योगिक दौरा:** यह श्रमिकों को अन्य उद्योगों में प्रक्रियाओं, कार्य वातावरण और प्रबंधन प्रथाओं को समझने के साथ-साथ नवीनतम तकनीकों के बारे में जानने का अवसर देता है।
- **शैक्षणिक आधार:** चीन में 1980 के दशक की शुरुआत में जनसँख्या में वस्फोटक वृद्धि हुई। कम्युनिस्ट युग के दौरान चीन में स्थापित प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता ने देश को तेज़ी से विकास के लिये तैयार किया।
 - [राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020](#) के तहत, भारत को अपने बच्चों को एक मजबूत शैक्षणिक आधार प्रदान करना चाहिये।
- **विश्व स्तरीय अधिगम स्तर:** वर्ष 2018 से, चीनी स्कूली छात्रों ने [आर्थिक सहयोग और विकास संगठन \(OECD\)](#) द्वारा आयोजित [अंतरराष्ट्रीय छात्र मूल्योंकन कार्यक्रम \(PISA\)](#) में विश्व के सर्वश्रेष्ठ से बेहतर प्रदर्शन किया है।
 - भारत को अपने शिक्षा प्रणाली को उन्नत करना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चे विश्व स्तरीय अधिगम के मानक को प्राप्त कर सकें।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना(PLI)

- **PLI योजना** की परिकल्पना घरेलू वनरिमाण क्षमता को बढ़ाने, आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिये की गई थी।
- मार्च 2020 में शुरू की गई इस योजना ने शुरुआत में तीन उद्योगों को लक्षित किया:
 - मोबाइल और संबद्ध घटक वनरिमाण
 - वदियुत घटक वनरिमाण और
 - चकितिसा उपकरण।
- बाद में इसे 14 क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया।
 - PLI योजना में घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में वनरिमाण के लिये वित्तीय पुरस्कार मिलते हैं, जो पाँच वर्ष तक के लिये उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर होता है।
- **लक्षित क्षेत्र:** यह 14 क्षेत्र हैं मोबाइल वनरिमाण, चकितिसा उपकरणों का वनरिमाण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स,

वर्षिष इस्पात, दूरसंचार एवं नेटवर्कगि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिकि उत्पाद, वाइट गुड्स (एसी और एलईडी), खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद, सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी, तथा ड्रोन् व ड्रोन् घटक ।

■ योजना के तहत प्रोत्साहन:

- दयि जाने वाले प्रोत्साहनों की गणना वृद्धशील बकिरी के आधार पर की जाती है ।
- उन्नत रसायन सेल बैटरी, कपड़ा उत्पाद और ड्रोन् उद्योग जैसे कुछ क्षेत्रों में, दयि जाने वाले प्रोत्साहन की गणना पाँच वर्षों की अवधि में की गई बकिरी, प्रदर्शन एवं स्थानीय मूल्य संवर्धन के आधार पर की जाएगी ।

नषिकरष

भारत के वैश्वकि आर्थकि महाशक्ति बनने के पूर्वानुमान के बावजूद, इसकी असफल शकिषा प्रणाली और सम्मानजनक रोज़गार प्रदान करने में असमर्थता के कारण इसकी संभावनाएँ धूमलि हैं । जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संबोधति करना महत्त्वपूर्ण है, एक संतुलति दृष्टिकोण जो वदिशी वर्षिषज्जता को प्रोत्साहति करता है और साथ ही साथ घरेलू शकिषा और तकनीकी कौशल को बढ़ाता है, आवश्यक है ।

तेज़ी से बढ़ती वैश्वकि अर्थव्यवस्था में प्रतस्पर्धा करने हेतु, भारत को अपनी मानव पूंजी की कमियों और यथार्थवादी आर्थकि रणनीतियों को तत्काल हल करना चाहयि ताकि बढ़ती बेरोज़गारी और अवकिसतिता से बचा जा सके ।

दृष्टमैन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारतीय वनिरिमाण उद्योग के वकिस में वदिशी वर्षिषज्जता और ज्ञान के महत्त्व पर चर्चा कीजयि ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

2017-18:

प्रश्न. दक्षणि पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था एवं समाज में प्रवासी भारतीयों को एक महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिनी है । इस संदर्भ में दक्षणि-पूर्व एशिया में प्रवासी भारतीयों की भूमिका का मूल्यनरूपण कीजयि । (2017)

प्रश्न. श्रम-प्रधान नरियात के लक्ष्य को प्राप्त करने में वनिरिमाण क्षेत्र की वफिलता का कारण बताइए । पूंजी-प्रधान नरियात के बजाय अधिक श्रम-प्रधान नरियात के लयि उपाय सुझाइए । (2017)

प्रश्न. “भारत में जनांकिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिकि ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शकिषति, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती । सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोज़गार-योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लयि कौन-से उपाय कयि हैं? (2016)